

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

86

समक्ष : श्री एम०के० सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3939-एक/2016 विरुद्ध आदेश दिनांक  
17-11-2016 - पारित द्वारा तहसीलदार नौगाँव जिला छतरपुर -  
प्रकरण क्रमांक 91 अ-68/2015-16

जयदेव सिंह बुन्देला बल्द बोविन्द सिंह

ग्राम मउ सहानिया तहसील नौगाँव

जिला छतरपुर मध्य प्रदेश

---आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन

---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री लखन सिंह धाकड़ )

(अनावेदक के पैनल लायर श्री डी०के० शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 9 - 12 - 2016 को पारित)

तहसीलदार नौगाँव जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक  
91 अ-68/ 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 17-11-2016  
के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के  
अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई।

2- प्रकरण का सारौंश यह है कि पटवारी हलका मउ  
ने तहसीलदार नौगाव को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मउ  
स्थित भूमि खसरा नंबर 1314/3 रकबा 0.699 हैक्टर , जो मध्य  
प्रदेश शासन शासकीय भवनों हेतु आरक्षित है , पर जयदेव सिंह  
बुन्देला पुत्र गोविन्दसिंह ने अतिक्रमण करके 30X40 वर्गफुट पर  
मकान व दुकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। तहसीलदार





नौगाँव ने प्रकरण क्रमांक 91 अ-68/ 2015-16 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक को सुनकर आदेश दिनांक 17-11-2016 पारित किया एवं आवेदक पर 20,000/-रु. अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये बेदखली के आदेश दिये। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3- निगरानी मेमो में अंकित आधारों के क्रम में आवेदक के अभिभाषक ने लेखी तर्क प्रस्तुत किये। शासन के पैनल लायर के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- निगरानी मेमो के तथ्यों एवं उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा की गई बहस पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि पटवारी द्वारा तहसीलदार नौगाँव को अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है प्रस्तुत रिपोर्ट पर से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1314/3 रकबा 0.699 हैक्टर मध्य प्रदेश शासन द्वारा भवनों के निर्माण हेतु आरक्षित है अर्थात् वाद विचारित भूमि का मद भवन निर्माण हेतु सुरक्षित है जिसके 30X40 वर्गफुट पर मकान व दुकान बनाकर आवेदक ने अतिक्रमण किया है तब क्या निर्मित पक्के मकान एवं दुकान के भाग को संहिता की धारा 248 के अंतर्गत अतिक्रमण-स्वरूप हटाया जा सकता है ?

अनुजराम विरुद्ध म0प्र0शासन 1969 राजस्व निर्णय 447 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत के आश्वासन पर, कि भूमि का पट्टा दिया जायेगा, मकान निर्माण सदभावनापूर्ण किया गया, ऐसा अतिक्रमण हटाने योग्य नहीं है। विचाराधीन प्रकरण में ग्राम पंचायत मउ ने आवेदक को दिनांक 16-4-1999 को भूखंड क्रमांक 13 रकबा 30X40 वर्गफुट पर मकान बनाने हेतु पट्टा प्रदान दिया है पट्टे की छायाप्रति तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न है। बेनीप्रसाद पाण्डेय विरुद्ध म0प्र0 राज्य 1980 रा0नि0 154



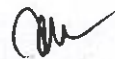


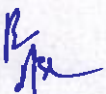
का न्याय दृष्टांत है कि आवेदक को ग्राम पंचायत ने पट्टा दिया जो इतालवी रजिस्टर में दर्ज है भवन निर्माण की ग्राम पंचायत की अनुमति है । राजस्व मण्डल ने तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 248 के अंतर्गत पारित बेदखली आदेश , एस0डी0ओ0 का अपीलीय आदेश तथा अतिरिक्त आयुक्त का अपीलीय आदेश दिनांक 9-9-76 निरस्त किया है एवं निगरानी स्वीकार हुई ।

विचाराधीन निगरानी प्रकरण की भी यही स्थिति है, किन्तु तहसीलदार नौगाँव ने आदेश दिनांक 17-11-16 पारित करते समय इन तथ्यों पर ध्यान न देने में भूल की है।

5/ प्रकरण में आये तथ्यों से प्रमाणित है कि ग्राम पंचायत मउ ने आवेदक को ग्राम मउ की भूमि खसरा नंबर 1314/3 के 30X40 वर्गफुट पर मकान बनाने हेतु पट्टा दिया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25-1-2007 को आवेदक को मकान बनाने की अनुमति भी प्रदान की गई है , तदुपरांत आवेदक ने ग्रामीण बैंक से ऋण लेकर मकान का निर्माण किया है। पूर्व में भी ग्राम न्यायालय में अतिक्रमण की शिकायत होने पर आदेश दिनांक 30-9-2004 से अतिक्रमण न होना मानकर प्रकरण निरस्त हुआ है तथा ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 30-9-2004 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी नौगाँव के समक्ष अपील हुई है जो प्रकरण क्रमांक 8/2004-05 अपील पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 4-4-2005 से निरस्त हुई है। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति तहसीलदार नौगाँव के प्रकरण में पृष्ठ 31 से 33 पर संलग्न है जिसके पद 3 का अंश उद्धरण इस प्रकार है -

” जहाँ तक गुण-दोष पर प्रकरण की स्थिति है उसमें उत्तरवादीगण को पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अंतर्गत






गठित प्रथम पंचायत में पट्टे दिये हैं, द्वितीय पंचायत ने उन्हें निरस्त नहीं किया है न ही किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें अवैध घोषित किया गया है ऐसे में पट्टेधारी को अतिक्रामक मानलना उचित प्रतीत नहीं होता है जिससे अधीनस्थ ग्राम न्यायालय का आदेश हस्तक्षेप योग्य प्रतीत नहीं होता है। ”

अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 4-4-2005 अपील निगरानी के अभाव में अंतिम Res-Judicata है जिसके विरुद्ध जाकर तहसीलदार को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में संहिता की धारा 248 के अंतर्गत पुर्नविचार करने अथवा वादग्रस्त भूमि में हस्तक्षेप करने के अधिकार नहीं है किन्तु उनके द्वारा इन अभिलेखों के देखे बिना प्रकरण क्रमांक 91 अ-68/ 2015-16 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 17-11-2016 से आवेदक के सम्बन्ध में दिये गये बेदखली आदेश को नियमानुसार होना नहीं माना जा सकता, जिसके कारण तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार नौगाँव जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 91 अ-68/ 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 17-11-2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं निगरानी स्वीकार की जाती है।

R  
AP

  
(एम0के0सिंह)  
सदस्य

राजस्व मण्डल  
मध्य प्रदेश ग्वालियर